भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1260

मंगलवार, 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग

1260. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः
श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण निकायों, उद्यमियों और स्व-सहायता समूहों द्वारा ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों की पहुंच और उपयोग के संबंध में हाल ही में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान देश में ई-कॉमर्स मंचों पर ग्रामीण उद्यमियों/उद्योगों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त विनिर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों से लाभान्वित लाभार्थियों विशेषकर महिलाओं और युवाओं का आन्ध्र प्रदेश सहित योजनावार, राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है और उनकी कुल संख्या कितनी है;

(घ) आन्ध्र प्रदेश सहित राज्यवार और जिलावार और विशेषकर एलुरू जिले में उक्त योजनाओं के प्रयोजनार्थ इस अवधि में आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान देश में ऐसी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई संवर्धनात्मक कार्यकलाप/अभियान चलाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): सरकार ने ग्रामीण निकायों, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करने तथा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

(i) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपने स्वायत्त संगठनों, नामत: राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के जरिए ग्रामीण उद्यमियों सहित समाज के सभी वर्गों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें की हैं।

एनआईईएसबीयूडी ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से जनवरी 2020 से मार्च 2023 तक 10 राज्यों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित की, जिसका उद्देश्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम, मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराकर लक्षित समूहों के बीच उद्यमिता की भावना का निर्माण करना, बढ़ावा देना तथा संवर्धन करना था। एनआईईएसबीयूडी ने 10 आकांक्षी जिलों के 98 ब्लॉकों से 98 मास्टर ट्रेनर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग और उद्यमिता विकास संबंधी मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण तथा 10 आकांक्षी जिलों के 101 ब्लॉकों में डिजिटल मार्केटिंग

और उद्यमिता विकास पर महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की है, जिसमें 1993 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अलावा, संस्थान ने इस परियोजना के तहत 693 एसएचजी को अमेज़न, 744 एसएचजी को फ्लिपकार्ट और 830 एसएचजी को विला मार्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने में सहायता की है।

एमएसडीई ने लक्षित लाभार्थियों में ई-कॉमर्स के लाभों की समझ और ज्ञान को बढ़ाने तथा ई-कॉमर्स में नवीनतम रुझानों, उपकरणों और तकनीकों के संबंध में लक्षित लाभार्थियों को व्यापक प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करने के लिए वर्ष 2024 में आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) के तहत "क्षमता निर्माण और सहायता दृष्टिकोण के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग पर आधारभूत स्तर के उद्यमियों को सशक्त बनाने" को भी स्वीकृति दी है। दिनांक 31.01.2025 की स्थिति के अनुसार, इस परियोजना के तहत भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) द्वारा 3000 प्रशिक्षुओं के लिए ई-कॉमर्स संबंधी सात दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण पूरा हो चुका है।

(ii) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) डीपीआईआईटी (ने डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क) ओएनडीसी (की अग्रगामी पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य , डिजिटल कॉमर्स को सभी के लिए उपलब्ध कराना है ,जिससे कि प्रत्येक विक्रेता, एमएसएमई, व्यापारी, किसान और उपभोक्ता, डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से बाजार तक पहुंच बनाए, इसके भागीदार बने और इसका लाभ उठा सके। ओएनडीसी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों में शामिल है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-:

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के नेटवर्क का उपयोग, ओएनडीसी के माध्यम से भारत के प्रत्येक गांव को राष्ट्रीय डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। 4 लाख से अधिक ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के अपने नेटवर्क के साथ - ओएनडीसी के माध्यम से सीएससी, ग्रामीण भारत में सहायता आधारित ई-कॉमर्स की क्षमता को फलीभूत कर रहा है। यह एकीकरण ग्रामीण नागरिकों को एक विस्तृत ई-कॉमर्स नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे वीएलई के लिए उद्यमिता के अवसरों और आय में वृद्धि होती है।
- कृषि मंत्रालय, एफपीओ को सहायता प्रदान कर रहा है तथा उनके लिए ओएनडीसी के माध्यम से देशभर में बाजारों तक पहुंच को आसान बना रहा है। 7000से अधिक एफपीओ पहले ही ओएनडीसी-अनुकूल एप्लीकेशंस में शामिल हो चुके हैं, जिससे वे भारत के 1 60से अधिक शहरों में अपनी उपज का विक्रय करने में सक्षम हैं, जिसमें अभिनव संयुक्त डिजीटल मांग सृजन पहलों की सहायता ली गई है। यह पहल किसानों और एफपीओ उद्यमों को डिजिटल रूप से सशक्त करती है, और उन्हें बाजार तक पहुंच प्रदान करती है।

- प्रसार भारती वैश्विक सेवा दायित्व निधि) यूएसओएफ) के तहत भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए ओएनडीसी के जरिए ग्रामीण भारत के लिए ओटीटी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ ब्रॉडबैंड सेवाओं को जोड़ने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसमें प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म 'वेव्स' पर खरीदारी को लागू करना शामिल है। यह ओनडीसी के डिजिटल कॉमर्स फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत है ताकि उत्पादों और सेवाओं की बिक्री को लागू किया जा सके, जिससे ग्रामीण विक्रेताओं के लिए डिजिटल दूरी को कम किया जा सके।
- एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन (टीम) स्कीम शुरू की है, जिसे 5 लाख छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को ओएनडीसी में शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अंतर्गत यह निर्धारित है कि 50% लाभार्थी महिला-स्वामित्व

वाले उद्यम होंगे। इस प्रकार, इस पहल से भारत के एमएसएमई क्षेत्र की ताकत और विकास क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे एक अधिक मजबूत, समावेशी डिजिटल कॉमर्स ईकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा।

- सिडबी जैसी वित्तपोषण एजेंसियां और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ), ग्रामीण, सत्व जैसी समाज-सेवी एजेंसियां, स्वयं सहायता समूहों को डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाने और ओएनडीसी के माध्यम से अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बना रही हैं। बीएमजीएफ ने ओएनडीसी के माध्यम से 1 मिलियन महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया है।
- वर्तमान में ओएनडीसी नेटवर्क पर लगभग 7 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता मौजूद हैं। चूंकि ओएनडीसी कोई प्लेटफ़ॉर्म या मार्केटप्लेस न होकर एक नेटवर्क है, इसलिए यह लाभार्थियों पर जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र नहीं करता है।
  - ओएनडीसी ने ओपन डिजिटल सत्रों के माध्यम से ओएनडीसी पर 300+ घंटे का वर्चुअल प्रशिक्षण और 200+ घंटे का तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसमें 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स, छात्रों, व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों आदि ने भाग लिया है।
  - ओएनडीसी ने विक्रेताओं (विशेष रूप से पहली बार आने वाले विक्रेताओं) को डिजिटल कॉमर्स में सफल होने में मदद करने के लिए 14 भाषाओं में एक पुस्तिका तैयार की है और इसे व्यापक रूप से वितरित किया जा रहा है।
  - ओएनडीसी ने भारतीय भाषाओं में ऐप डेवलपमेंट और ई-कॉमर्स को बेहतर बनाने के लिए भाषिनी के साथ साझेदारी की है।
  - ओएनडीसी सहायक - व्हाट्सएप बॉट "ओएनडीसी सहायक" को 5 भाषाओं में लॉन्च किया गया, जिसका विस्तार 22 भाषाओं तक किया जाएगा, ताकि विक्रेताओं और खरीदारों को ओएनडीसी के बारे में जानकारी मिल सके।
  - ओएनडीसी ने पूरे भारत में ई-कॉमर्स को अपनाने के संबंध में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को सक्षम बनाने के लिए यूजीसी तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के साथ मिलकर ओएनडीसी अकादमी शुरू की है।

(iii) स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए विपणन सहायता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ने जुलाई, 2023 में एसएचजी द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स पहल के रूप में ई-सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ई-कॉमर्स मोबाइल ऐप, ई-सरस का प्रयोग एसएचजी की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए अधिक प्रभावी प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) की इस पहल का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ, प्रामाणिक हस्तशिल्प और हथकरघा के विपणन को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के साथ मिलकर एसएचजी और एसएचजी सदस्यों के खाद्य उत्पादों, हस्तशिल्प और हथकरघा आदि के क्यूरेटिड उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से संपर्क के जरिए बढ़ावा देने हेतु विभिन्न माध्यमों जैसे जेम, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी), फ्लिपकार्ट, मीशो और जियो मार्ट जैसी अन्य ई-कॉमर्स से जुड़ी पहलें की हैं।

31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एसएचजी उत्पादों को ई-सरस प्लेटफॉर्म में शामिल किया गया है। ई-सरस, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) पर विक्रेता नेटवर्क भागीदार के रूप में भी सक्रिय है। महिला एसएचजी को मौजूदा विपणन पहलों के साथ एकीकृत करने के लिए 7-8 अगस्त, 2024 को दो दिवसीय ट्रेनर्स का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 88 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में शामिल एसएचजी सदस्यों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1260 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में शामिल किए गए एसएचजी सदस्यों की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	**राज्य**	*** ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में शामिल किए गए एसएचजी सदस्यों की राज्यवार संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	6462
2.	असम	1276
3.	बिहार	350
4.	गोवा	1200
5.	गुजरात	250
6.	हरियाणा	126
7.	जम्मू और कश्मीर	116
8.	झारखंड	98
9.	कर्नाटक	800
10.	केरल	3000
11.	महाराष्ट्र	10803
12.	मणिपुर	156
13.	नागालैंड	16
14.	सिक्किम	3000
15.	तमिलनाडु	2289
16.	त्रिपुरा	30
17.	उत्तराखंड	110
18.	उत्तर प्रदेश	2253
19.	पश्चिम बंगाल	102
कुल		32437

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा संसूचित

*****